मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता । दुनिया के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । दुनिया को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233

नई सीरीज नम्बर 13 | जुलाई 1989 | 50 पैसे

मजदूर आन्दोलन और तकनोलॉजी

1983 में बाटा फरीदाबाद में यूनियन ने ट्रायल के नाम पर मैनेजमेंट से जब आटोमेशन की एग्रीमेंट की तब हमने कहा था कि पूँजीवाद में मजदूरों के लिये आटोमेशन का मतलब छँटनी और वर्क लोड में बढोतरी ही हैं । इस पर उस एग्रीमेंट के पक्षधर कुछ सज्जनों ने पूछा था, "तो क्या आप नई-नई आधुनिक मशीनों के खिलाफ हैं ?"

इधर भिलाई स्टील प्लान्ट की लोहा-पत्थर खदानों में मशीनीकरण के खिलाफ आठ हजार ठेका मजदूरों के नेताओं ने आवाज उठाई है । उन लोगों ने कताई मिल और हथकरघा (खड्डी) के मेल जैसे अर्ध-मशीनीकरण को मजदूरों के हित में एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है ।

वैसे, मजदूर आन्दोलन से परे कुछ भलेमाणस भी हैं जिन्होंने तकनोलॉजी के सवाल को समाज का सबसे अहम सवाल बना रखा है । आमतौर पर भरे पेट वाले यह लोग "छोटे" का गुणगान करते हैं— इन्हें मिट्टी के घर, खड्डी पर कपड़ा बुनना, कुम्हार का चाक, लुहार का हथौड़ा, आदिवासियों का जंगलवास रोमांचित करते हैं। यह भलेमाणस भिलाई खदानों के ठेका मजदूरों के लीडरों के मशीनीकरण-विरोध का पुरजोर समर्थन करते हैं ।

मजदूर आन्दोलन और तकनोलॉजी के सवाल को "चिनगारी" से जुड़े नागपुर के एक मित्र ने सटीक ढंग से रखा । उन्होंने कहा कि पूँजीवादी व्यवस्था में कोई भी तकनोलॉजी क्यों न हो, उसका इस्तेमाल मजदूरों के शोषण के लिए ही होता है । पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर चाहे हथौड़ों से पत्थर तोड़ें चाहे क्रैशरो पर काम करें, वे रहते शोषित-पीड़ित मजदूर ही हैं। इसलिए मजदूर आन्दोलन का काम पूँजीवादी व्यवस्था में इस या उस तकनोलॉजी का पक्ष लेना नहीं है । मजदूर आन्दोलन का काम है पूँजी के नुमाइन्दों के मजदूरों पर हमलों के खिलाफ संघर्ष को शक्तिशाली बनाना । इसलिए ध्यान मजदूर संघर्ष को ताकतवर बनाने पर केन्द्रित करना चाहिए। मजदूरों को सवाल को इस तरह पेश करना चाहिए : संघर्ष को मजबूत करने के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए ?

पूंजी एक सामाजिक सम्बन्ध है और मजदूरों के खून-पसीने पर मुटियाना पूँजी का जीवन है । पूँजी के नुमाइन्दे पूँजी के फलने-फूलने में आड़े आते मजदूरों के विरोध से निपटने के लिए ही नरम या गरम हथकण्डे अपनाते हैं । इसलिए मजदूरों का काम पूँजीवाद को सुचारु रूप से चलाना नहीं है । पूँजी के नुमाइन्दों को यह सलाह देना कि कौन से तरीके से बिना ज्यादा झंझट के मजदूरों का शोषण किया जा सकता है, यह मजदूर आन्दोलन का काम नहीं है । पूँजी के नुमाइन्दे खाई में कूद रहे हों तो हम उन्हें कहेंगे कि कूये में कूदो ।

मजदूर आन्दोलन का लक्ष्य पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़-फेंकना है । रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ों में चाय के जरिए कुम्हारी को जिन्दा रखने की जार्ज फर्नांडीज की स्कीम, सरकार माई-बाप द्वारा बुनकरों को सहायता आदि असल में दस्तकारों को झटके की जगह हलाल करने के पूँजीवादी तरीके हैं । फर्नांडीज के कुल्हड़ों और राजीव गाँधी कम्प्यूटरों में चुनना हमारा काम नहीं है । पूँजीवादी व्यवस्था अब सड़-गल गई है और इसे दफना कर ही मानव आगे बढ़ सकते हैं ।

गलतफहमी न रहे इसलिए दोहरा दें, मजदूरों का बेहतर वर्किंग कंडीशनों के लिए लड़ना रोजी-रोटी के लिए उनके संघर्ष की तरह ही जीवन के लिए मजदूरों का संघर्ष है ।

मजदूर आन्दोलन के बदलते तेवर

फरवरी अंक में हमने धनबाद के कोयला खदान मजदूरों द्वारा बिचौलियों को दुत्कार कर दिसम्बर 88 में स्वयं संगठित एक संघर्ष का जिक्र किया था। साथ ही हमने चक्रधरपुर के रेलवे मजदूरों द्वारा सूदखोरी-विरोधी संघर्ष का भी विवरण दिया था जिसमें हजारों देहाती गरीब भी शामिल हो गए थे और जून 87 में रेल रोकने की तैयारी को देख कर सत्ताधारी झुके थे। मार्च अंक में हमने कानपुर के कपड़ा मजदूरों द्वारा 22 से 27 फरवरी 89 तक रेलें रोक कर एक जीत हासिल करने का विवरण दिया था। इधर कलकत्ता से बंगला और हिन्दी में प्रकाशित श्रमिक इस्तेहार के मई-जून 89 अंक में एक रेलवे मजदूर का खत छपा है जो मजदूर आन्दोलन के बदलते तेवर की एक और झलक दिखाता है ।

धनबाद-आसनसोल रेल लाइन पर बिहार में छोटा अम्बाना रेलवे स्टेशन है । पास ही कंक्रीट स्लिपर फैक्ट्री है । आजकल लकड़ी के स्लिपर की जगह रेलवे द्वारा कंक्रीट स्लिपर लगाए जा रहे हैं । छोटा अम्बाना कंक्रीट स्लिपर फैक्ट्री धकाधक चल रही है पर "मुनाफा नहीं हो रहा है" के नाम पर वहाँ काम कर रहे 350 मजदूरों को मिनिमम वेज भी नहीं दिया जाता था । बिहार में 18 रुपये रोज का न्यूनतम वेतन है पर इन मजदूरों को 12 रुपये रोज के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। छुट्टी-वुट्टी और अन्य सुविधा की तो बात ही नहीं थी । मैनेजमेंट के दमन-शोषण का विरोध करने के लिये मजदूरों ने संगठित होना शुरू किया । इस पर फरवरी 89 के अन्त में 12 मजदूरों का गेट बन्द कर दिया गया । तब मार्च में मजदूरों ने हड़ताल शुरू की । अपने संघर्ष की धार तीखी करने के लिए मजदूरों ने रेलें रोकने का फैसला किया । पुलिस की धौंस-धपट्टी के बावजूद 18 अप्रैल 89 को 339 अप गाड़ी रोक कर मजदूरों ने संघर्ष को तेज किया । रेलवे के एक बड़े साहब के इस आश्वासन पर कि वह 6 दिन में मामला तय करवा देगा, मजदूरों ने रेलों के रास्ते से रुकावटें हटा ली । पर दूसरे दिन ही मैनेजमेंट ने पुलिस और फुटकर गुंडों की मदद से फैक्ट्री से माल निकालने की कोशिश की । मजदूरों ने उनकी पार नहीं पड़ने दी । पुलिस द्वारा फैक्ट्री से माल निकलवाने की कोशिश जारी रखने पर 29 अप्रैल को एक हजार देहाती गरीब तीर-धनुष से लैस होकर फैक्ट्री के मजदूरों से आन मिले । डी० सी० को आना पड़ा और पुलिस को फैक्ट्री से हटाना पड़ा । मजदूरों ने एक जीत हासिल की है। 4 मई से फैक्ट्री खुल गई है—मजदूरों को 18 रुपए रोज, 15 दिन की छुट्टी व स्वास्थ्य सुविधायें मिलेंगी । "श्रमिक इस्तेहार" का पता है :

सुभाष राय, पी-45 एस० एन० राय रोड, कलकत्ता-700038

—×—

केल्विनेटर के मजदूरों से

29 जून को पहली बार केल्विनेटर में वास्तविक हड़ताल करके केल्विनेटर के वर्करों ने संघर्ष की अपनी इच्छा का सबूत दिया है । मजदूर अगर पहली गढ़ी जीत लेंगे तो यह आगे की लड़ाई में उनका स्तम्भ बनेगी । और मैनेजमेंट को भी यह साफ-साफ दीख रहा है । इसलिए हालात ऐसी बनी हैं कि मामला पहले कदम पर ही तूल पकड़ता लगता है । पुचकारने की पालिसी इस बार सफल होती नहीं लगती इसलिए मैनेजमेंट मजदूरों के उभरते संघर्ष को कुचलने की तैयारी में जुटी है। 450 कैजुअलों को 29 को काम पर न आने के नाम पर फैक्ट्री से निकाल कर उसने पहला कदम उठा भी लिया है । इन हालात में केल्विनेटर के मजदूरों को अपने संघर्ष को मजबूत करने के लिए कदमों पर विचार करना चाहिए । हमारे विचार से कुछ कदम जो केल्विनेटर के मजदूरों को तत्काल उठाने चाहिए वे हैं—

1. शिफ्ट छूटने पर मजदूर जलूस निकालें । बल्लबगढ़ प्लान्ट के वर्कर तहसील तक और इंडस्ट्रियल एरिया वाले मजदूर डी सी, डी एल सी दफ्तरों तक । जलूस जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा रहेगा ।

2. साइड मीटिंगों और आम सभाओं के जरिए सब मजदूरों को संघर्ष की स्थिति और कदमों पर विचार-विमर्श में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिये ।

3. आस-पास की ईस्ट इंडिया-गवर्नमेंट प्रेस-थर्मल-बाटा-ब्राउन बाउरी-आटोमीटर जैसी बड़ी और सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियों के मजदूरों से तालमेल बढ़ाने के लिए केल्विनेटर मजदूरों को कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाले दिनों में संघर्ष को फैलाया जा सके ।

केल्विनेटर के मजदूरों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि लेबर डिपार्टमेंट पुलिस और मन्त्री मैनेजमेंट के साथी हैं । इन सब की मिली-जुली ताकत से टक्कर लेने के लिए जितनी जरूरी केल्विनेटर के मजदूरों की एकता है, अन्य

हमारे लक्ष्य हैं—1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुँचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनिया के मजदूरों की एकता के लिए काम करना और इसके लिए आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बँटाना । 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिए काम करना । 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिए काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को तालमेल के लिए हमारा खुला निमन्त्रण है । बातचीत के लिए बेझिझक मिलें । टीका-टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे ।

सम्पर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन० आई० टी० फरीदाबाद—121001

फैक्ट्रियों के मजदूरों का केल्विनेटर के मजदूरों द्वारा शुरु किए संघर्ष में शामिल होना भी उतना ही जरूरी है।

—×—

ईस्ट इण्डिया कॉटन

दस साल के बाद ईस्ट इण्डिया के मजदूरों ने 8 जून को मैनेजमेंट-गुण्डा गिरोहबन्दी के खिलाफ पहली जीत हासिल की। और मजदूरों की यह जीत एक दुखद घटना के बाद हुई।

ईस्ट इण्डिया के खास करके प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग प्लान्ट में पूँजीवादी सुरक्षा नियमों की भी इस कदर अनदेखी की जा रही है कि यह व्यवस्था अगर इतनी सड़-गल गई न होती कि व्यवस्था के कर्त्ता-धर्त्ता ही खुलेआम अपने नियमों को तोड़ते हैं तो सुरक्षा के नाम पर ही कम्पनी में ताला लग जाता। पर ऐक्सीडैंटों में मरते मजदूर हैं और मैनेजमेंट नुक्सान के नाम पर बीमा से बढ़-चढ़कर पैसे लेती है। इसलिए इधर-उधर जेबों में पैसे डालकर कम्पनी की गाड़ी चल रही है।

आठ जून को रात के एक बजे ऐक्सीडैंट में एक मजदूर की मौत हो गई। लाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, डाक्टरों ने मृत घोषित कर उसे तत्काल श्मशान के लिए रवाना कर दिया। ईस्ट इण्डिया के लिए यहाँ तक यह सामान्य घटना थी। लगता है कि तभी दाल फ्राई गुण्डा गिरोह ने लाश पर पाँच-दस हजार की रोटी सेंकने की तिकड़म रची। सुबह चार बजे लाश श्मशान की बजाय फैक्ट्री के अन्दर ले आई गई। मजदूर लाश के इर्द-गिर्द इक्ट्ठे हो गए। 6·30 सुबह की शिफ्ट के मजदूर भी जुड़ गए। खबर फैलने पर ईस्ट इण्डिया के पावरलूम और डाबर प्लान्टों के मजदूर भी आ कर लाश के इर्द-गिर्द इक्ट्ठे हो गए। अन्य शिफ्टों के मजदूरों के आने से 8 बजते-बजते 3-4 हजार मजदूर लाश के पास जमा हो गए। दाल फ्राई और बड़े-छोटे छुटभैय्ये मैनेजमेंट से नेगोसियेशन का ड्रामा करने लगे—यहाँ तक खेल दाल फ्राई के सोचे मुताबिक चल रहा था और हजारों मजदूरों की भीड़ बस भीड़ ही थी। पर तभी पावरलूम का एक वर्कर वहाँ पहुँचा और उसने मूक मजदूरों को वाणी दी। उस मजदूर के भाषण ने दाल फ्राई गिरोह के हाथों से तोते उड़ा दिए। हजारों मजदूरों ने एक स्वर में मृत मजदूर के परिवार को कम्पनी द्वारा एक लाख रुपये मुआवजा देने की माँग की। एल. एम. एस. का जिला प्रधान जो कि यूनियनदाल फ्राई का लीगल एडवाइजर है, उसने अपने बिगड़े खेल को सवारने की कोशिश की। हजारों मजदूरों ने लात-मुक्कों से उसकी अक्ल कुछ ठिकाने लगा दी। इस पर सालों से खा-पी रहे 100-150 वाले दाल फ्राई गिरोह की भी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। पुलिस के आने पर ही उनके एक मुखिया ने पावरलूम मजदूर को धमकियाँ देकर अपनी भड़ास निकाली। पर हजारों के मजदूरों तेवरों ने पुलिस और मैनेजमेंट को हिला दिया। दाल फ्राई के साथ हिस्सा-पत्ती करने वाले परसनल मैनेजर के हाथ से निकल कर मामला बड़े साहब के हाथों में गया। मृत श्रमिक के रिश्तेदारों द्वारा मैनेजमेंट की 60 हजार की बात स्वीकार करते ही 100-150 को छोड़कर सब मजदूर इक्ट्ठे फैक्ट्री से बाहर चले गए। ऐक्सीडैंट में मरने वाले मजदूर के परिवार को कम्पनी अपनी तरफ से अब तक कुछ नहीं देती थी।

गत 10-12 साल में ईस्ट इण्डिया के मजदूरों के गुस्से ने एक के बाद दूसरे मसीहा को जन्म दिया है और हर बार मजदूरों को धत्ता बताकर मसीहा मैनेजमेंट की गोटी बना है। बिचौलियों पर आस को छोड़, एक साथ 21 माँगें उठाकर आर-पार की लड़ाई की बजाय रोजाना की छापामार लड़ाई खुद चलाकर आज की हालात में मजदूर बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। जुझारू मजदूर पूँजी के नुमाइन्दों के गले में हड्डी बनकर पूँजीवादी व्यवस्था को पलटने के संघर्ष में आज बेहतर योगदान दे सकते हैं।

—×—

एक मजदूर का खत

मजदूरों के लीडर भी मैनेजमेंटों के लीगल एडवाइजर भी

प्लाट नम्बर 112 सैक्टर 6 की रेबरटोस फैक्ट्री में 35 मजदूर काम करते हैं, 13 परमानेन्ट और 1 से 4 साल से काम कर रहे 22 कैजुअल। 8 जून को मजदूरों ने 625 वाले न्यूनतम वेतन की माँग की। 9 जून को मैनेजमेंट ने 7 वर्करों को गेट पर रोक दिया। लन्च में 15 मजदूर उनके समर्थन में बाहर आ गए।

मजदूरों ने यूनियन दफ्तरों और लेबर डिपार्टमेंट में भाग-दौड़ की। 24 जून को यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि "मजदूर मोर्चा" का एक बड़ा लीडर मैनेजमेंट का लीगल एडवाइजर है। और वह वर्करों को मौजूदा कानून के मुताबिक सहुलियतें देने के भी खिलाफ दलीलें दे रहा था। ध्यान देने की बात यह भी है कि "मजदूर मोर्चा" का यह लीडर एक समय फरीदाबाद एच. एम. एस. का अध्यक्ष भी था।

सुभाष, फोर्ड का डिसमिस वर्कर

बाटा

बाटानगर, बंगाल में चार महीने लॉकआउट के बाद नवम्बर 88 में यूनियन से समझौता करके मजदूरों को झुकाने में सफल हुई मैनेजमेंट को दमन-शोषण की खुली छूट मजदूरों ने नहीं दी है। इसका सबूत 19 अप्रैल से 1 मई तक की हड़ताल है। एक आम मजदूर को छोटी-सी बात पर डिसमिस कर देने के खिलाफ मजदूरों ने एक के बाद दूसरी डिपार्टमेंट बन्द करनी शुरू कर दी और इस प्रकार तीन दिन में दस हजार मजदूर हड़ताल में शामिल हो गये। काम चालु रखने की कहने आये यूनियन लीडरों को मजदूरों ने भगा दिया। बाटानगर फैक्ट्री में हड़ताल फैलाने तक बाटा मजदूर सफल रहे पर इससे आगे क्या ? संघर्ष को ताकतवर कैसे बनाया जाये ताकि बाटा मैनेजमेंट और उसकी पीठ पर हाथ रखे पूँजीवादी तन्त्र से टक्कर ली जा सके ? बाटा मजदूर इन सवालों पर अटक गये। उन्होंने न तो अन्य मजदूरों को संघर्ष में शामिल कर अपनी ताकत बढाने के प्रयास किये और न ही कानपुर के कपड़ा मजदूरों की तरह रेलवे या सरकार के अन्य किसी महत्वपूर्ण अंग पर चोट करके अपना संघर्ष तीखा किया। ऐसे में बिचौलियों को फिर मौका मिला। मैनेजमेंट-यूनियन नेताओं की बातचीत के बाद 2 मई को मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। [सामग्री "श्रमिक इस्तेहार" से ली है।]

इधर बाटा फरीदाबाद में वालेन्ट्री रिटायरमेंट में एजेन्टी व अन्य कारणों से यूनियन लीडरों में जूतम-पजार इस कदर बढी कि जून में कार्यकारिणी के 9 सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। इस पर कानूनी दाँव-पेच में दोनों गुट फँस गये और अब वे लीपा-पोती के चक्कर में हैं। पर बाटा मजदूरों के लिये इन गुटों की सिर-फुटौवल से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं मैनेजमेंट की वालेन्ट्री रिटायरमेंट और तीन साला एग्रीमेंट को 19 महीने आगे धकेलने की स्कीमें।

बाटानगर में मैनेजमेंट और यूनियन ने समझौता किया है कि वहाँ सितम्बर 89 में होने वाली एग्रीमेंट अब अप्रैल 91 में होगी। और फरीदाबाद तथा अन्य जगहों पर होने वाली एग्रीमेंटों को 19 महीने टालने के लिये आजकल जाल बुना जा रहा है। बिचौलियाँ ने इधर एक चाल चल भी दी है। उन्होंने फेडरेशन के गड़े मुर्दे को फिर उखाड़ा है। दलीलें दी जा रही हैं कि पहले संयुक्त माँग-पत्र दिया जाए और उस पर फैसले के बाद ही अलग-अलग यूनिट अपने-अपने माँग-पत्र दें। संयुक्त माँग-पत्र पर चर्चा हो इसके लिए पहले फैडरेशन को मान्यता का सवाल उठाया जाएगा और उसके लिए ड्रामों का सिलसिला चलेगा। इस प्रकार यह मजदूरों की आँखों में धूल झोंककर 19 महीने गुजारने की तिकड़म लगती है। इस बीच मजदूर एकता की दुहाई वे लोग देंगे जो बाटानगर में लॉकआउट के समय फरीदाबाद में ओवरटाइम करवा कर मैनेजमेंट के हाथ मजबूत कर रहे थे। इन हालात में, हमारे विचार से बाटा फरीदाबाद के मजदूरों को एक कदम तो यह उठाना चाहिए कि उनका डिमान्ड चार्टर समय पर दिया जाए और डिमान्डें मनवाने के लिए कदम उठाये जायें। फैडरेशन और संयुक्त माँग-पत्र की कार्यवाही जरूर की जाए पर इन्हें पूर्वशर्त बनकर मजदूरों को उल्लु बनाने की फिराक में बैठे लोगों से बचें।

—×—

एस्कोर्ट्स में चुनाव के नाम पर ड्रामा

मई दिवस पर मीटिंग में बुलाने पर 12 हजार सदस्यों में से जब कुल 17 सदस्य ही आए तब एस्कोर्ट्स यूनियन के प्रधान ने इसे मुद्दा बनाकर इस्तीफा दे दिया था। वास्तव में मामला यह है कि गत 6-7 साल से एक के बाद दूसरे बहाने से मजदूरों पर वर्क लोड बढवाने में यूनियन अध्यक्ष के रोल ने एस्कोर्ट्स मजदूरों में उसकी साख मिट्टी में मिला दी है। मैनेजमेंट व यूनियन अध्यक्ष के लिए यह बेहद जरूरी हो गया कि वे इस बारे में कुछ करें। इस्तीफा इसमें एक कदम के तौर पर आया।

नए अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हुआ और क्योंकि अध्यक्ष पहले भी कई बार इस्तीफे देकर वापस ले चुका था इसलिए मजाकों को हद से बढ़ने से रोकने के लिए इस बार चुनाव करवाने का फैसला पक्का रखा गया। पर चुनाव के नाम पर ड्रामा किया गया। अध्यक्ष के संगी लीडरों और लठैतों ने वोट न पड़ने देने के लिए पूरा जोर लगाया, इसका असर भी पड़ा। फिर भी 3300 वोट पड़े और एक नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। नया अध्यक्ष न तो टिकने लायक लगता है और न ही उसे टिकने दिया जायेगा।

एस्कोर्ट्स मजदूरों को ड्रामेबाजों के शगूफों में उलझने के बजाय लगातार बढ़ाए जा रहे वर्कलोड और छँटनी की लटकती तलवार के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में ड्रामे कुछ ज्यादा ही होंगे और मजदूरों पर बड़े हमले करने के लिए मैनेजमेंट कदम उठायेगी।

स्वत्वाधिकार व सम्पादक शेरसिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अशोक कम्पोजिंग एजेन्सी द्वारा, मानस प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली-110031 में मुद्रित।